BCCI BULLETIN
BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES
Vol. XXXXVI | 15th April, 2015 | No. 7

चैम्बर के साथ हुए संवाद में आयुक्त, पटना प्रमंडल ने कहा

समय दें, समस्याएं दूर होंगी

कार्यक्रम में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। उनकी बाँयीं ओर क्रमशः डॉ० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद, आयुक्त पटना प्रमंडल, श्री शीर्षत कपिल अशोक, निगमायुक्त एवं श्री पी० के० दास, एस०पी० ट्रैफिक। दाँयीं ओर क्रमशः श्री सुभाष कुमार पटवारी, उपाध्यक्ष, श्री मधुकर नाथ बरेरिया, उपाध्यक्ष, श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल, महामंत्री, डॉ० रमेश गाँधी, कोषाध्यक्ष, श्री शशि मोहन, पूर्व उपाध्यक्ष एवं अन्य।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 25 मार्च, 2015 को डॉ० ई०एल०एस०एन० बाला प्रसाद, भा०प्र०से०, आयुक्त,पटना प्रमंडल के साथ संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर श्री शीर्षत कपिल अशोक, नगर निगम आयुक्त एवं श्री पी० के० दास, भा०पु०से० आरक्षी अधीक्षक, यातायात भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने की।

अपने स्वागत सम्बोधन में श्री साह ने कहा डॉ० बाला प्रसाद भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। इन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। इनका कार्यकाल काफी शानदार रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि डॉ० बाला प्रसाद के प्रशासनिक मार्गदर्शन में पटना प्रमंडल का चहुंमुखी विकास अवश्य होगा और ''स्वच्छ एवं सुन्दर पटना'' की परिकल्पना साकार होगी।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि पटना की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उन समस्याओं से अवगत हैं। मैं आयुक्त सहित यहाँ उपस्थित पदाधिकारियों का ध्यान पटना की यातायात समस्याओं एवं शहर की मूलभूत नागरिक सुविधाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, यथा :-

• पटना की यातायात सुविधा में सुधार हेतु उच्च स्तरीय निर्णय लेने की आवश्यकता • ट्रैफिक को वन-वे किया जाये। इससे गाड़ियाँ सुगमता से चलेगी। कोलकाता और बनारस की तंग गलियों में जब गाड़ियां चलायी जा सकती है तो यहां क्यों नहीं • यातायात बाधित रहने की जानकारी देने वाला डिस्प्ले बोर्ड का प्रयोग अन्य सड़कों पर भी किया जाए • ट्रैफिक पुलिस एक ही जगह दिखाई देती है, उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए • पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एरिया में दिन में वाहनों का प्रवेश दानापुर की तरफ से होने दिया जाये। इसे वहाँ के एसडीओ ने रोक दिया है • जामवाले स्थानों पर वॉकी टॉकी से लैस जवान लगाये जायें, क्रेन की भी व्यवस्था रहे • पार्किंग की समस्या भी रोड जाम को बढ़ाती है, डिवाइडर और नये बन रहे ओवर ब्रीज के नीचे पार्किंग की व्यवस्था की जाये • नगर निगम द्वारा सफाई और सौंदर्यीकरण के मामले में कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही है • वार्ड में एक सफाई समिति का गठन किया जाये जो निगम को फीड बैक देते रहे • रात में कूड़ा उठाया जाये • कूड़े को डंप करने की भी उचित व्यवस्था हो कूड़े से बायो फर्टिलाइजर बनाने की इकाई स्थापित की जाये, साथ ही बारिश आने वाली है, जल निकासी की समुचित एवं स्थायी व्यवस्था हो • महत्वपूर्ण स्थानों पर टैक्सी स्टैंड बने, चालकों को नाम की पट्टी के साथ वर्दी भी हो। पार्किंग स्थलों को चिन्हित कर निःशुल्क एवं सशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की जाये • गंगा के घाटों को विकसित एवं सौन्दर्यीकृत किया जाये • दाह संस्कार के लिए घाटों पर समुचित व्यवस्था हो • पार्कों के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था की जाय।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए ट्रैफिक एसपी श्री पी० के० दास ने कहा कि पटना सिटी क्षेत्र में ट्रैफिक सुधार के लिए वहाँ ट्रैफिक थाना स्थापित किया जायेगा। यह इलाका वर्षों से भीषण जाम की समस्या से त्रस्त है। हमारे पास मानव संसाधन की कमी है, इसके चलते सारा ध्यान राजधानी के प्रमुख स्थलों की यातायात व्यवस्था सुचारू करने में लग जाता है। इसलिए पटना सिटी में ट्रैफिक थाना की काफी आवश्यकता है। राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। प्रस्ताव पास होते ही वहाँ की समस्या का समाधान हो जायेगा। इसके पहले ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए हमने योजना बनायी है कि प्रत्येक सप्ताह उस इलाके में अभियान

चलाया जायेगा जिससे कुछ हद तक जाम का समाधान होगा।

उन्होंने आगे कहा कि मानवता के नाते अब सभी रास्ते रोककर एंबुलेंस को हर हाल में निकाला जायेगा। न्यू डाकबंगला रोड को वन वे करने पर गंभीरतापूर्वक विचार हो रहा है। पूर्व में भी गाँधी मैदान के चारो ओर सड़क को वन वे करने पर कमिश्नर की बैठक में विचार हुआ था जिसे फिलहाल कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। वीणा सिनेमा के पास जून के बाद वन वे कर दिया जायेगा। अभी प्राथमिकता जीरो टॉलरेंस जोन पर सबको परिवहन नियम का पालन कराने पर है। चिड़ियाखाना से कोतवाली थाना तक लेन में गाड़ियों को चलाया जा रहा है। श्री दास ने कहा कि अगले दो माह में पटना ट्रैफिक में बड़ा बदलाव दिखेगा।

नगर निगम आयुक्त श्री शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि ज्ञापन में जो भी मुद्दे आये हैं उस सम्बन्ध में कहना है कि इस वर्ष जल जमाव एवं सफाई की समस्या से छुटकारा मिल जायेगा। इसके लिए कार्य योजना बनाई गयी है। इस सम्बन्ध में लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किया जायेगा। घर-घर कूड़ा उठाने की भी कार्य योजना बनायी जा रही है। निगमायुक्त ने कहा कि हमारे पास अच्छे प्रशिक्षित कर्मियों की कमी है। सफाई हेतु काम्पैक्टर का भी उपयोग किया जा रहा है। जो मजदूर ठीक से सफाई नहीं करते हैं उन्हें ठीक से काम करने को निर्देशित करेंगे। नगर निगम का ग्रिवांस सिस्टम थोड़ा कमजोर है। इससे गड़बड़ी हो रही होगी। शहर में 36 सम्प हाउस हैं उसमें 25 जल बोर्ड और 11 नगर निगम देखरेख करता है। नाला उड़ाही के बाद जो अवशिष्ट रहते हैं उसे भी शीघ्र हटाने की व्यवस्था की जायेगी। दाह-संस्कार हेतु तीन इलेक्ट्रीक शवदाह गृह चालू हैं। साफ-सफाई हेतु समुचित धयान दिया जायेगा। मृत पशुओं के निस्तारण हेतु बैरिया में व्यवस्था की जा रही है। गंगा घाट के सौन्दर्यीकरण का कार्य River Front वाले कर रहे हैं। ऑटो स्टैण्ड का जो मुद्दा उठाया गया है उसे मैंने नोट कर लिया है। मौर्या लोक में शौचालय की व्यवस्था हेतु निदेश दिया जायेगा। न्यू मार्केट दुकानदार कल्याण समिति के बारे में व्यवस्था की जायेगी। आने वाले वित्तीय वर्ष में वेंडर जोन पर काम करेंगे। ऑन लाइन होल्डिंग टैक्स में गड़बडी को ठीक करने के लिए कदम उठाएंगे। इस मामले को देखने के लिए उप नगर आयुक्त श्री राजीव रंजन जी नोडल ऑफिसर हैं वे इसे ठीक करेंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि हर वार्ड में कमिटी गठित है, उसमें बार्ड पार्षद अध्यक्ष हैं, उन्हें भी अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं।

आयुक्त पटना प्रमंडल डॉ० बाला प्रसाद ने सदस्यों द्वारा उठाई गयी समस्याओं एवं ज्ञापन के मुद्दों पर कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बातचीत का दौर जारी रहे तो समस्याएँ एक के बाद एक समाप्त हो जायेंगी। समय दें समस्याएँ दूर होंगी। एक नागरिक एवं एक पदाधिकारी के रूप में तीस सालों से पटना में हूँ। यहाँ की समस्याओं से मैं भी अवगत हूँ। शहरी नागरिकों की नगर निगम के बारे में जो समस्याएँ हैं, काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए नगर निगम पूर्ण प्रयासरत है। यातायात सुगम करना मेरी प्राथमिकता है। इसमें अवश्य सुधार होगा।

डॉ० बाला प्रसाद ने मुख्य बाजार, मंडी की समस्याओं पर चैम्बर द्वारा दिये गए सुझाव हेतु धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं निर्देश दूंगा और स्वयं मॉनीटरिंग भी करूंगा। अन्य समस्याएँ भी दूर होंगी। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक संघों के रूप में उनका भी कुछ दायित्व है। सरकार ही सभी कुछ नहीं कर सकती। अत: व्यावसायिक संघों से उन्होंने व्यक्तिगत अपील किया कि वे शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने में भागीदार बनें। सरकार व समाज के सहयोग से ही समस्याएँ दूर हो सकती है। डॉ० बाला प्रसाद ने कहा कि हम समस्याओं के प्रति गंभीर हैं और फर्क आपको बहुत जल्द दिखेगा। वार्त्तालाप निरंतर जारी रहनी चाहिए।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री युगेश्वर पाण्डेय, श्री बांके रस्तोगी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन, पूर्व कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, पटना सिटी व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह, श्री अनिल पचीसिया, श्री सच्चिदानन्द, न्यू मार्केट व्यवसायी कल्याण समिति के श्री सुमंत सिकदर, श्री नवीन गुप्ता, चैम्बर के पूर्व महामंत्री श्री ए० के० पी० सिन्हा एवं लाइब्रेरी एण्ड बुलेटिन उप समिति के चेयरमैन श्री रामचन्द्र प्रसाद ने डॉ० बाला प्रसाद के समक्ष यातायात एवं नगर निगम से सबंधित समस्याएँ बतायी एवं सुझाव भी दिये।

कार्यक्रम में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी एवं श्री मधुकर नाथ बरेरिया, कोषाध्यक्ष डॉ० रमेश गाँधी एवं महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल सहित चैम्बर के सदस्य एवं मीडिया बन्धु काफी संख्या में उपस्थित थे। महामंत्री श्री ओम प्रकाश टिबड़ेवाल के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।

मनोनयन

श्री ओ० पी० साह, अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

चैम्बर में कॉइन मेला आयोजित

कॉइन मेले में उपस्थित चैम्बर के पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, श्री ए०एम० अंसारी एवं आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के अधिकारीगण।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 30 मार्च, 2015 को आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के सहयोग से कॉइन मेला का आयोजन किया गया जिसमें 1/-, 2/-, 5/- एवं 10/- के सिक्के तथा दस रूपये का नये नोट भी व्यवसायियों को उपलब्ध कराये गये।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि चैम्बर को कई सदस्यों से यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि बाजार में सिक्कों की कमी के कारण उन्हें व्यवसाय में असुविधा हो रही है। उक्त आलोक में चैम्बर ने पहल करते हुए व्यवसायियों की सुविधा हेतु आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के सहयोग से चैम्बर प्रांगण में कॉइन मेला का आयोजन कराया जिसमें काफी संख्या में व्यवसायियों ने आवश्यकतानुसार विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्के एवं नोट प्राप्त किया। इस मेले में 10 लाख रूपये का सिक्का एवं नोट सदस्यों को उपलब्ध कराया गया।

चैम्बर अध्यक्ष ने कहा कि व्यवसायियों की सुविधा के लिए पूर्व में भी चैम्बर द्वारा इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता रहा है। चैम्बर का यह प्रयास होगा कि व्यवसायियों की सुविधा के लिए कुछ समय के अन्तराल पर इस प्रकार के मेले का आयोजन आगे भी होता रहे जिससे कि बाजार में सिक्कों का संतुलन बना रहे।

कॉइन मेले में चैम्बर की ओर से पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुरेश प्रकाश गुप्ता, श्री ए० एम० अंसारी तथा आई०सी०आई०सी०आई० बैंक की ओर से फ्रेजर रोड शाखा के उप प्रबंधक एवं आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के मुद्रा तिजोरी शाखा, पटना के अधिकारी उपस्थित थे।

बस्ती में लगेगा बोरिंग पंप: ओ. पी. साह

मारवाड़ी युवा मंच पटना सिटी शाखा के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह 1.4.2015 को चौक स्थित भामाशाह ट्रस्ट भवन में आयोजित किया गया। समारोह का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष नंद किशोर यादव ने किया। उन्होंने कहा कि मंच के कार्यकर्ता अपने कार्यो के साथ ही सामाजिक कार्यो में भी शिरकत करते हैं। मंच हमेशा नगर के सामाजिक और धार्मिक कार्यो में अपना योगदान करता रहा है। समारोह के मुख्य अतिथि बिहार चैम्बर ऑफ कार्मस एण्ड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ. पी. साह ने कहा कि नगर के विकास में भी मंच का सहयोग रहा है। श्री साह ने मंच के माध्यम से स्लम बस्ती में समरसेबल बोरिंग कराने की घोषणा की। समारोह को मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल वर्मा, कमल नोपानी ने भी संबोधित किया। उपाध्यक्ष वर्मा ने मंच सिटी शाखा के 11वीं बार चुने गये अध्यक्ष संजीव देवड़ा सहित सचिव पंकज लोयनका और कार्यकारिणी के 21 सदस्यों को शपथ ग्रहण कराया। मंच संचालन मनोज झुनझुनवाला ने किया।

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.4.2015)

एकजुट रहें सभी व्यवसायी : श्री ओ० पी० साह

मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सह पदस्थापना समारोह का उद्घाटन मोतीहारी के बी० के० गार्डेन प्रांगण में रविवार दिनांक 5 अप्रील, 2015 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने किया। समारोह की अध्यक्षता मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री महेश चन्द्र लाल ने की। मोतीहारी चैम्बर के महासचिव श्री रामस्वरूप तिवारी ने पूरे सत्र का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का उद्घाटन करते बिहार चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। (बाँयें से तीसरे)। उनकी दाँयीं ओर स्थानीय विधायक श्री प्रमोद कुमार एवं मोतीहारी चैम्बर के महासचिव श्री राम स्वरूप तिवारी तथा बाँयीं ओर मोतीहारी चैम्बर के अध्यक्ष श्री महेश चन्द्र लाल एवं उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री मोतीलाल छापड़िया।

समारोह को संबोधित करते हुए श्री साह ने कहा कि सभी व्यवसायी संगठन एकजुट रहें ताकि किसी भी परिस्थिति का सामना मजबूती के साथ किया जा सके। हम व्यवसायी भारत की रीढ़ हैं। हमारे द्वारा किये गये टैक्स भुगतान से विकासात्मक कार्यों को मूर्तरूप दिया जाता है। साथ ही समाज सेवा और रोजगार सृजन में भी व्यवसायियों का महत्वपूर्ण योगदान है। चैम्बर अध्यक्ष ने संगठन में अधिक से अधिक व्यवसायियों को जोड़ने पर भी बल दिया। श्री साह ने कहा कि यदि मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स जमीन खरीद कर अपना भवन निर्माण करता है तो बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हर संभव मदद करेगा।

मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सह पदस्थापना समारोह को संबोधित करते बिहार चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह

कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि स्थानीय विधायक श्री प्रमोद कुमार ने कहा कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय एवं मोती झील का विकास आवश्यक है। उन्होंने देश में व्यवसायियों की भूमिका को अहम बताया। नये सत्र 2015-16 के नव -निर्वाचित अध्यक्ष श्री बिरेन्द्र कुमार जालान, उपाध्यक्ष श्री प्रशांत जायसवाल एवं श्री अंकुर कुमार, महासचिव श्री संजय जायसवाल एवं कोषाध्यक्ष श्री राजकुमार लखौटिया ने पद-भार ग्रहण किया।

समारोह के दौरान मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा विशिष्ट नागरिक का सम्मान श्री नारायण मुनि को, विशिष्ट सरकारी पदाधिकारी का सम्मान मोतीहारी मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव को एवं विशिष्ट पुलिस पदाधिकारी का सम्मान रंगदारी सेल के प्रभारी श्री ललित विजय तिवारी को प्रदान किया गया।

इस अवसर पर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व उपाध्यक्ष श्री शशि मोहन एवं पूर्व महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय विशेष रूप से आमंत्रित थे।

मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से आमजनों एवं व्यवसायियों के लिए ऑक्सीजन सिलेन्डर का लोकापर्ण किया गया। जिसे नि:शुल्क जरूरतमंदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

पदभार ग्रहण करने के बाद मंच पर आसीन मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री विरेन्द्र कुमार जालान (बाँयें) एवं उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री मोतीलाल छापड़िया।

समारोह के दौरान श्री नारायण मुनि को विशिष्ट नागरिक का सम्मान देते बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह।

इस समारोह में नगर पार्षद श्री प्रकाश अस्थाना, पूर्व मंत्री श्री ब्रज किशोर सिंह, उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री मोतीलाल छापड़िया, रक्सौल टेक्सटाइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री अरूण कुमार गुप्ता, सीतामढ़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ बिजय सर्राफ, इण्डो-नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अधयक्ष श्री राज कुमार गुप्ता, बलुआ व्यवसायी संघ के अध्यक्ष श्री संजय रमण, मोतीहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य सहित प्रबुद्ध नागरिक एवं प्रेस बंधु काफी संख्या में उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन महासचिव श्री संजय जायसवाल ने किया।

नई वेबसाइट पर काम करेगा वाणिज्यकर विभाग

वाणिज्य कर विभाग का वेबसाइट पहली अप्रैल से सीटीडी बिहार. जीओवी. इन से बदलकर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू बिहार कॉमर्शियलटैक्स.जीओवी.इन हो जाएगा। अब सुविधा डी-8 निकालने के लिए व्यापारियों को नई वेबसाइट पर काम करना होगा। टीसीएस ने इसका मॉड्यूल तैयार किया है। विभाग ने पुरानी वेबसाइट संचालित करने वाली एजेंसी बेस्ट को निर्देश दिया है कि वह डी-8 से संबंधित सभी डाटा तय फॉर्मेट में विभाग को उपलब्ध कराए, जिससे विभाग के डाटा बेस में इसे स्थापित किया जा सके।

प्रत्येक व्यवसायी को माल की खरीद-बिक्री, प्राप्ति व प्रेषण से संबंधित त्रैमासिक व वार्षिक विवरण इसमें देना होता है। समीक्षा में पाया गया कि अधिकांश व्यवसायी रिटर्न में कई बॉक्स व कॉलम अधूरा छोड़ देते हैं। विशेषकर त्रैमासिक रिटर्न में बॉक्स-बी व सी तथा वार्षिक रिटर्न में आरंभिक भंडार व अंतिम भंडार का विवरण नहीं रहता है। विभागीय प्रधान सचिव ने सभी अंचल प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी व्यापारियों को सूचित कर दें कि यदि उनके द्वारा सही व पूर्ण रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो उनपर जुर्माना लगाया जाएगा। **(साभार : दैनिक जागरण, 11.4.2015)**

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी निर्बंधित व्यवसायियों एवं परिवहनकर्त्ताओं को सूचित किया जाता है कि वाणिज्य-कर विभाग का हेल्प डेस्क प्रत्येक कार्य दिवस में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराहन तक कार्यरत है।

हेल्प डेस्क की सेवा प्राप्त करने हेतु Toll Free Number- 18003456102 अथवा 0612-2233512, 2233513, 2233514, 2233515, 2233516 पर प्रत्येक कार्य दिवस की उक्त कार्यावधि में सम्पर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ई-मेल आई. डी. vattcs.helpdesk@gmail.com पर ई-मेल भेज कर भी समस्याओं का निवारण कराया जा सकता है।

PR 14681 D (वित्त) 2014-15 वाणिज्य-कर आयुक्त-सह प्रधान सचिव
बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2015)

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
आवश्यक सूचना

एतद् द्वारा सभी निर्बंधित व्यवसायियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.04.2015 के प्रभाव से प्रपत्र RT-1 एवं RT-V onilne दाखिल करते समय Box-B एवं Box-C को भरा जाना अनिवार्य होगा। यह अनिवार्यता दिनांक 01.04.2015 के उपरान्त दाखिल किये जाने वाले किसी भी अवधि के RT-1 एवं RT-V पर लागू होगा।

अत: सभी निर्बंधित व्यवसायियों से अनुरोध है कि दिनांक 01.04.2015 के उपरान्त दाखिल किये जाने वाले सभी RT-1 एवं RT-V upload करने के क्रम में Box-B एवं Box-C अनिवार्य रूप से सही प्रकार से प्रविष्ट कर upload करें।

PR 14681 D (वित्त) 2014-15 वाणिज्य-कर आयुक्त-सह प्रधान सचिव
बिहार, पटना

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2015)

₹ 1000 के सामान पर भी इंट्री टैक्स

राज्य में अब 1000 रुपए के माल पर भी प्रवेश कर लगेगा। पहले यह सीमा 25 हजार थी। इस परिवर्तन से सरकार को 125 करोड़ रुपए से अधिक के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है। यदि सामान की खरीद इलेक्ट्रानिक कॉमर्स (ई-कॉमर्स) या फिर खरीदा गया सामान किसी अन्य मार्फत मंगाया गया होगा तो उसे डिलीवर करने वाला एजेंट ही इंट्री टैक्स की राशि उपभोक्ता से वसूल कर सरकारी खजाने में जमा करेगा।

गौरतलब है कि 12 मार्च को वित्त मंत्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, ने अपने बजट भाषण में वित्त विधेयक का जिक्र किया था। इसके तहत कर वसूली के तीन अधिनियमों को युक्तिसंगत बनाने की बात कही गई थी। सदन के सदस्यों के बीच विधेयक की प्रतियां सर्कुलेट की गई। विधेयक पर चर्चा 16 अप्रैल को होगी। इंट्री ट्रैक्स में संशोधन की मूल वजह ट्रांसपोर्ट, कूरियर व ई-कॉमर्स के मार्फत सामान मंगाने का बढ़ता चलन है। अब इस काम में लगी एजेंसियों को प्रत्येक माह उपभोक्ताओं को डिलीवर किए गए सामान और उस पर वसूली गई कर राशि का हिसाब सरकार को देना होगा।

खत्म होगा बिहार में बाहर का माल बेचने का खेल : राज्य में चोरी छिपे माल मंगाने का खेल खत्म होगा। सरकार, संशोधन के जरिए वैट अधिनियम 2005 के उस 'चोर दखाजे' को ही बंद करने जा रही है जिससे उसे चपत लगती थी। इस काम में वे कारोबारी शामिल थे जो बाहर से माल तो दूसरे राज्य के लिए बुक करते थे पर उतार लेते थे बिहार में। यह सब कर से बचने के लिए होता था। नए प्रावधानों के तहत दूसरे प्रदेश का सामान लादने वाले ट्रक को एक जांच चौकी से राज्य की सीमा में प्रवेश करने के 24 से 72 घंटे के अंदर दूसरे चेक पोस्ट से निकल जाना होगा।

तीन गुना पेनाल्टी, ड्राइवर व मालिक पर कार्रवाई भी : यदि तय अवधि में ट्रक बाहर नहीं निकला तो मान लिया जाएगा कि उस पर लदा माल बिहार में ही उतार लिया गया। ऐसे ट्रकों के नम्बर को ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। दोबारा यदि वही ट्रक माल लाद कर बिहार की सीमा में प्रवेश करेगा तो वह वाणिज्य कर विभाग की कार्रवाई की जद में आ जाएगा और तीन गुना पेनाल्टी देने के बाद ही छूटेगा। कार्रवाई कारोबारी पर तो होगी ही, ट्रक मालिक भी चपेट में आएंगे। **(दैनिक भास्कर, 1.4.2015)**

एक अप्रैल से हर चीज, हर सेवा महंगी नहीं हो रही

आम बजट में सर्विस टैक्स 12.36 से 14% किया गया है,
20 अप्रैल से 8 मई के बीच हो सकता है लागू

एक अप्रैल यानी बजट घोषणाओं पर अमल शुरू होने की तारीख। इस बार हमें प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी घोषणा है सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी। जो 12.36% से बढ़कर 14 फीसदी किया जाना है। लेकिन यह लागू तभी होगा जब सरकार की ओर से अधिसूचना यानी आदेश जारी होंगे। अभी संसद में छुट्टी है। वित्त विधेयक पर बहस पूरी नहीं हुई है। बजट सत्र का दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होगा, जो 8 मई तक चलेगा। संसद से बिल पास होने के बाद ही अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना की तारीख से ही बढ़ा हुआ टैक्स लगेगा।

हालांकि कुछ सेवाओं को सर्विस टैक्स के दायरे में लाया गया है। कुछ को निकाला भी गया है। ये फैसले 1.4.2015 से ही लागू होंगे। लेकिन इन पर 12.36% की दर से ही टैक्स लगेगा। यह बात बजट दस्तावेज में साफ की गई है।

इन पर बढ़ा टैक्स का दायरा : • विमान किराया। पहले किराये के 40% पर सर्विस टैक्स लगता था। अब 60 % पर लगेगा। • म्यूचुअल फंड-चिट फंड में निवेश महंगा। लॉटरी टिकट विभागीय टेलीफोन भी सर्विस टैक्स के दायरे में आ गए हैं। • रेल या सड़क से खाने-पीने की चीजों के ट्रांसपोर्ट पर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। अब चावल, दाल, आटा, दूध और नमक को छोड़ बाकी चीजों की दुलाई पर टैक्स लगेगा। • एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, थीम पार्क पर भी सर्विस टैक्स लगेगा। म्यूजिक कंसर्ट या एंटरटेनमेंट शो का टिकट 500 रु. से ज्यादा का है तो सर्विस टैक्स लगेगा।

इन पर राहत : • म्यूजियम, जू नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, अभयारण्य के टिकट पर लगने वाला सर्विस टैक्स आज से खत्म। • वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, एंबुलेंस सेवाएं। फल-सब्जियों की रिटेल पैकिंग पर भी अब टैक्स नहीं लगेगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 1.4.2015)

साइलो से भंडारण क्षमता बढ़ाएगा एफसीआई

नई तकनीक तीन साल में 2000 करोड़ रुपए के निवेश की
एफसीआई ने बनाई है योजना

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) गेहूँ और चावल के लिए अपनी पारंपरिक भंडारण क्षमता को "साइलो" स्टोरेज के जरिए 20 लाख टन और बढ़ाएगा। अगले तीन -चार साल में इनके निर्माण पर 2,000 करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत होगी। इनका निर्माण जन-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत किया जाएगा।

उन्होंने बताया, "साइलो" स्टोरेज स्टील ढांचा होता है। इसमें चार बेलनाकार बड़े टैंक होते हैं। हर टैंक की क्षमता 12,500 टन होती है। इनमें बिना बोरी के अनाज लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। इनका निर्माण निजी भागीदार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए फाइनेंस और इन्हें ऑपरेट करने का काम भी वही देखेगा, जबकि इन पर स्वामित्व एफसीआई का होगा। निगम इन पर 30 साल के लिए किराये की गारंटी मुहैया कराएगा।

एफसीआई ने देश में विभिन्न जगहों पर ऐसे 11 "साइलो" बनाने के बारे में अध्ययन किया है। इनमें से पाँच के लिए जल्द आवेदन मंगाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं: साहनोवाल, कोटकपूरा (पंजाब), नरेला (दिल्ली), कटिहार (बिहार) और चांगसारी (असम)। "साइलो" कॉम्प्लेक्स के साथ रेलवे को जोड़ना जरूरी होगा।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 1.4.2015)

एक से ज्यादा लोग तो एटीएम नहीं देगा नोट

पीएनबी के एटीएम से अगर रूपये निकालने हैं तो अकेले जाएं। एक से अधिक लोग के अंदर रहने पर एटीएम रुपये की निकासी बंद कर देगा। बैंक प्रबंधन ने फ्रॉड रोकने के लिए अपने एटीएम में ई-सर्विलांस व विशेष सॉफ्टवेयर लोड किये हैं।

नई तकनीक : • एटीएम खुद बोलेगा, 'एक से अधिक हैं, कृपया बाहर जाएं • 11 जिलों के एटीएम में पीएनबी ने लगाया विशेष सॉफ्टवेयर। **(हिन्दुस्तान, 28.3.2015)**

एक रुपये का नोट जारी करेगा रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही एक रुपये का करेंसी नोट जारी करेगा। ये नोट भारत सरकार द्वारा मुद्रित किए जाएंगे। इसके अग्रभाग पर वित्त सचिव राजीव महर्षि का हस्ताक्षर रहेगा। इसके पिछले भाग में एक रुपये के सिक्के के चित्र पर वर्ष 2015 के साथ गवर्मेंट ऑफ इंडिया अंकित रहेगा। इसके अगले भाग में गुलाबी हरा और पिछले भाग में अन्य रंगों का प्रयोग किया जाएगा। इस बात की जानकारी भारतीय रिजर्व बैंक, बिहार-झारखंड के प्रबंधक प्रवीण कुमार ने दी। **(हिन्दुस्तान, 14.3.2015)**

एसबीआई देगा सबसे सस्ता पर्सनल लोन

देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने होम लोन के ब्याज पर पर्सनल लोन देने की पेशकश की है। इसके साथ ही बैंक महिला उपभोक्ताओं को ज्यादा सस्ता पर्सनल लोन मिलेगा। बैंक के मुताबिक उसके मौजूदा होम लोन के उपभोक्ता 10.15 फीसदी पर पर्सनल लोन ले सकते हैं जबकि महिला उपभोक्ताओं के लिए ब्याज दर 10.10 फीसदी होगी। साथ ही बैंक ने इसके लिए प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं लेने का फैसला किया है। हालांकि, प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लेने की पेशकश 31 मार्च 2015 तक के लिए ही है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 13.3.2015)**

14 बैंकों का खराब प्रदर्शन, सरकार नहीं रखेगी राशि

सूबे में कुछ बैंकों का वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदर्शन नहीं सुधर रहा है। चालू वित्तीय 2014-15 के दौरान 14 बैंकों का प्रदर्शन अच्छा नहीं होने के कारण इन्हें सरकार ने डिबार या रोक लगा दी है। इन बैंकों में किसी विभाग की सरकारी राशि जमा नहीं की जायेगी और अगर पहले से किसी बैंक में पैसे जमा हैं, तो उन्हें निकाल लिया जायेगा। इससे संबंधित आदेश वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव, डीएम, बोर्ड, राजकीय लोक उपक्रम समेत अन्य सरकारी संस्थानों के प्रमुख अधिकारियों को जारी कर दिया है। वित्त विभाग ने अपनी समीक्षा में पाया कि जिन बैंकों को डिबार किया गया है, इन्होंने वित्तीय प्रबंधन या वित क्षेत्र में निर्धारित न्यूनतम स्तर का प्रदर्शन भी नहीं किया है। वित्त विभाग की तरफ से तय मानक के अनुसार इन बैंकों ने प्रदर्शन के मापदंड में न्यूनतम 33 अंक भी प्राप्त नहीं किया है। बैंकों को दो श्रेणी में रख कर इनका मूल्यांकन किया जाता है। श्रेणी-1, इसमें वैसे बैंक रहते हैं, जिनकी शाखा शहरी और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में ही सिर्फ है। श्रेणी-2, वैसे बैंक इनकी शाखाएं शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण तीनों क्षेत्रों में हैं। दोनों तरह के बैंकों के वित्तीय प्रदर्शन का मूल्यांकन सरकार तीन स्तर पर करती है। इन तीनों बिन्दुओं पर अलग-अलग मार्किंग की जाती है। तीनों अंकों को मिला कर न्यूनतम 33 अंक आना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं होने पर बैंकों को डिबार कर दिया जाता है। साख जमा अनुपात (सीडी रेसियो), प्राथमिक क्षेत्र में ऋण देने का औसत और अर्द्धशहरी क्षेत्रों में ऋण का प्रवाह (श्रेणी-1 वाले बैंकों के लिए) या कृषि क्षेत्र में ऋण देने की स्थिति (श्रेणी-2 वाले के लिए)। इन तीन मापदंडों पर ही सभी बैंकों के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है। **(साभार : प्रभात खबर, 29.3.2015)**

इन्हें किया गया डिबार : आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विजया बैंक, जम्मू एवं कश्मीर बैंक, एसबीबीजे, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, वैश्य बैंक, कर्नाटका बैंक, बम्बे मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, तपेंदु मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक, यस बैंक, सिंडिकेट बैंक व आइडीबीआई बैंक। इनमें सिंडिकेट और आईडीबीआई बैंक श्रेणी-2 और शेष सभी श्रेणी-1 वाले बैंक हैं।

नहीं बंद होंगे बिहार के उद्योग

बिहार के औद्योगिक विकास के लिए अपना फंड हो : सेबी अध्यक्ष

बिहार के उद्योग अगर फंड के अभाव में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सेबी, सिड्बी और बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज ने मिलकर एक नया प्लेटफार्म बनाया है। ये वैसे सभी एसएमई उद्योगों की मदद करेगा जो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते हैं अथवा शेयर बाजार में सूचीबद्ध होना चाहते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष यू. के. सिन्हा ने 1.4.2015 को यह घोषणा की।

वे यहाँ एक स्थानीय होटल में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिड्बी की इसमें और अधिक भूमिका होगी, क्योंकि उसे मर्चेंट बैंकिंग का भी लाइसेंस प्राप्त हो चुका है। श्री सिन्हा ने आशा जतायी है कि वर्ष के अंत तक बिहार के कम से कम 5 से 10 उद्योग सूचीबद्ध हो जायेंगे। यहाँ के शोध संस्थाओं से उन्होंने अपील की कि वे चिह्नित कर बतायें कि बिहार में वैसे कौने से दस उद्योग हैं, जो सूचीबद्ध होने को तैयार हैं। सेबी उनके साथ विमर्श के लिए तैयार है। बिहार के औद्योगिक संगठनों से उन्होंने अनुरोध किया कि वे आपस में बैठकर विचार करें कि आईपीओ के प्रोसेस में जाने के लिए किस उद्योग को बढ़ाया जाय।

श्री सिन्हा ने कहा कि साफ्टवेयर के क्षेत्र में विश्व में भारत का स्थान चौथा है। अमेरिका के सिल्कन वैली में काम करनेवाले उद्यमियों में 90 प्रतिशत भारतीय है और उनमें भी सबसे ज्यादा बिहारी हैं। बिहार के लोग गुड़गांव, दिल्ली, बंगलुरू तथा विदेशों में जाकर अपना उद्यम स्थापित कर सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं। लेकिन उनमें जागरुकता का अभाव है।

सेबी अध्यक्ष ने कहा कि बिहार ने हमलोगों ने राज्य सरकार से भी बात किया है। हमने उनसे कहा है कि वे अपना एक फंड सेटअप करें, जिसका उपयोग यहाँ के औद्योगिक विकास में किया जा सके। इस अवसर पर सिड्बी के महाप्रबंधक एस. रामकृष्णन, बाम्बे स्टाक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ आशीष कुमार चौहान, आईवीसीए के अध्यक्ष अरविंद माथुर, सेबी के कार्यकारी निदेशक मुरलीधर राव, मुख्य महाप्रबंधक स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक के. जी. अल्लाई एवं बॉम्बे स्टाक एक्सचेंज के वरीय महाप्रबंधक गोपाल कृष्णन अइय्यर भी मौजूद थे।

(साभार : आज, 2.4.2015)

इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पर ध्यान

बिहार सरकार इस खंड में निवेश आकर्षिक करने के लिए हुई तत्पर

बिहार सरकार ने बिहार में इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण क्षेत्र में निवेशकों को जुटाने के लिए कमर कस ली है। इसके लिए उद्योग विभाग ने पटना के नजदीक राजगीर में एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का फैसला लिया है, जिसमें 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति के तहत निवेशकों को जमीन मुहैया कराई जाएगी।

संभावनाओं से भरे इस क्षेत्र का बिहार उठाएगा लाभ : • राज्य का उद्योग विभाग पटना से सटे राजगीर में 50 एकड़ में लगाएगा एक औद्योगिक क्षेत्र, इस कार्य में जापान से सहयोग का आश्वासन • राज्य सरकार खास तौर पर दूरसंचार हार्डवेयर निर्माण से जुड़ी कंपनियों को करना चाहती है आकर्षित • निवेशकों को दी जाएंगी रियायतें। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 26.3.2015)**

एक पावर सब स्टेशन बनाने के लिए मिल गई जमीन

गोलघर के नजदीक बनेगा, इसी महीने शुरू होगा काम

राजधानी के लोगों को क्वालिटी बिजली देने के लिए आरएपीडीआरपी योजना के तहत एक और पावर सब स्टेशन बनाने की मंजूरी मिली है। गाँधी मैदान स्थित गोलघर के समक्ष बनने वाले इस पावर सब स्टेशन को बनाने का काम अप्रैल से शुरू होगा। पेसू के प्रभारी जीएम दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि गांधी मैदान स्थित एसटीएफ कार्यालय में बनने वाले इस पावर सब स्टेशन से गोलघर, दुजरा, मंदिरी सहित आसपास के लगभग 50 हजार उपभोक्ताओं को क्वालिटी बिजली मिलेगी। वहीं, आशियानानगर, एसटी कैरेंस स्कूल व एनआईटी कैंपस में बनने वाले पावर सब स्टेशन के लिए जमीन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम के तहत राजधानी में कुल 5 पावर सब स्टेशन बनाने की योजना है। ट्रांसपोर्ट नगर पावर सब स्टेशन व सगुना पावर सब स्टेशन के चालू होने के बाद राजधानी में पावर सब स्टेशनों की संख्या 49 हो गई है।

ये हैं फायदे : • लो-वोल्टेज से मिलेगी मुक्ति • घरों में लगे इलेक्ट्रॉनिक सामान को जलने का नहीं रहेगा खतरा • वोल्टेज कम व ज्यादा नहीं होगा • एसी, कूलर चलाने में नहीं होगी परेशानी।

राजधानी की वर्तमान स्थिति : • उपभोक्ताओं की संख्या - 4.25 लाख • ग्रिड की संख्या - 09 • डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मरों की संख्या - 4500 • 33 केवी फीडर की संख्या - 28 • 11 केवी फीडर की संख्या - 166 • पावर सब स्टेशन की संख्या - 49 **(साभार : दैनिक भास्कर, 1.4.2015)**

कांटी थर्मल पावर से सितम्बर तक 610 मेगावाट बिजली

कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड (केबीयूएनएल) की तीसरी यूनिट से बिजली का उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू होने के बाद अब इसकी चौथी यूनिट पर काम शुरू हो गया है। चौथी यूनिट को इसी वर्ष सितम्बर माह तक शुरू कर लेने का दावा निगम के अधिकारी कर रहे है, यदि सबकुछ सामान्य रहा। फिलहाल तीसरी यूनिट से 195 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन आरंभ हो गया।

• 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन पहले से दो यूनिट से हो रहा था • 195 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन तीसरी यूनिट से शुरू • 195 मेगावाट की यूनिट के सितम्बर तक तैयार होने की उम्मीद। **(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 2.4.2015)**

एक करोड़ लोग बनेंगे हुनरमंद

सीएम बोले – काम की कमी नहीं, जरूरत है कौशल विकास की

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में एक करोड़ लोगों को हुनरमंद बनाया जायेगा। पांच साल का यह लक्ष्य है, जिसे वे वर्ष 2013 में शुरू किये थे। इस काम को मिशन मोड में करने से सफलता मिलेगी। सरकार ने 17 विभागों को इसमें जोड़ा है, जहाँ लोगों को कौशल विकास दिलाने का काम होगा। सीआइआइ के तत्वावाधान में आयोजित स्कील कॉन्वलेव कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि काम की कमी नहीं है। काम करने लायक लोगों की कमी है। काम करने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत है। कौशल विकास जरूरी है। राज्य में युवाओं की बड़ी आबादी है। उन्हें शिक्षित व प्रशिक्षित कर उनकी ऊर्जा शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा उतनी बड़ी फौज को संभालना मुश्किल होगा। लोग अवसर मिलने पर आगे बढ़ते हैं। कम ही लोग होते हैं, जो शुरू से तीक्ष्ण बुद्धिमान होते हैं। इसलिए जरूरी है कि सारा फोकस शिक्षा पर होना चाहिए। इसके अलावा जितने ट्रेनिंग संस्थान, उतने ही सिखानेवाले लोग चाहिए।

गुणवतापूर्वक ट्रेनिंग से कहीं भी मिल सकेगा रोजगार : मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद ट्रेनिंग का कोर्स देखेंगे। गुणवत्तापूर्वक ट्रेनिंग मिलने से लोग कहीं भी काम करने के लिए जा सकते हैं। ट्रेनिंग देनेवाले संस्थान को सर्टिफिकेट निर्गत करने में उल्लेख करना चाहिए कि अमुक चीज में वह ट्रेंड है। इससे रोजगार मिलना आसान होगा। सीआइआइ की भूमिका हैंड होल्ड की होनी चाहिए, उन्होंने श्रम विभाग के सचिव एस. सिद्धार्थ को काफी अनुभवी मानते हुए उनसे इस पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। स्किल्ड लोगों को रोजगार से जोड़ने की बात कही। सीआइआई ईस्टर्न रीजन के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने अपने विचार रखे। उद्योग विभाग के सीआइआइ के क्षेत्रीय निदेशक एस मुखर्जी उपस्थित थे। सीआइआइ बिहार स्टेट कार्उंसिल के अध्यक्ष एसपी सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

साल भर में सवा लाख से अधिक को मिला रोजगार : कार्यक्रम में श्रम संसाधन विभाग के मंत्री दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014-15 में नियोजन मेला के माध्यम से लक्ष्य एक लाख एक हजार से अधिक एक लाख 28 हजार युवक व युवती को रोजगार दिलाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में आइटीआइ संस्थान खोलने की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कौशल विकास का ट्रेनिंग देनेवाली संस्था को जगह उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने सीआइआइ के अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक कंपनियों में लोगों को रोजगार का अवसर पर मिले इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

(साभार : प्रभात खबर, 29.3.2015)

केन्द्र नुकसान भरपाई की विशेष व्यवस्था करे: मुख्यमंत्री

चौदह वें वित्त आयोग की अनुशंसा से बिहार को होने वाले नुकसान के संदर्भ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को जो मांग पत्र सौंपा है उसमें हर सेक्टर के लिए राशि की मांग की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार के संसाधनों में संभावित कभी की भरपाई के लिए विशेष व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त आंध्रप्रदेश की तर्ज पर बिहार को जो विशेष सहायता देने की बात कही गई है उसके तहत एक लाख 7887 करोड़ केंद्र बिहार को दे। श्री नीतीश प्रधानमंत्री से मिले थे।

किस मद में कितनी राशि चाहिए : • दीघा-सोनपुर रेल सह सड़क पुल व ऊर्जा प्रक्षेत्र की लंबित योजनाओं के लिए 650 करोड़ • पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कि अवशेष 8284 करोड़ • 250 से अधिक आबादी वाले बसावटों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने को 32600 करोड़ • कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र के विकास को अगले पांच वर्षों के लिए 41587 करोड़ • सूबे के 6633 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन तथा सभी 8398 पंचायतों में उपस्कर की व्यवस्था के लिए 7285 करोड़ • जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूल मिशन के तहत स्वीकृत योजनाओं व लंबित योजनाओं को पूरा करने को 750 करोड़ • बौद्ध, जैन, सूफी, रामायण सिख व गाँधी परिपथ में आधारभूत संरचना के निर्माण को 5912 करोड़ • पटना में मेट्रो रेल योजना के कार्यान्वयन को 10500 करोड़

ये भी मांग की : • प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोलने व पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने को केंद्र आर्थिक मदद करे • हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी को शीघ्र चालू करने के लिए केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे • माल ढुलाई के लिए पटना में ड्राईपोर्ट व उसके निकट एक और हवाई अड्डा बने • इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साईंटिफिक एजुकेशन एंड रिसर्च, ट्रिपल आईटी, बागवानी विश्वविद्यालय तथा आपदा प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान बिहार में खुले। **(साभार : हिन्दुस्तान, 28.3.2015)**

मोबाइल पर हाजिर 'सरकार'

देश में 'ट्विटर संवाद' सेवा शुरू

डिजिटल इंडिया अभियान में अगला कदम रखते हुए केंद्र सरकार ने 25.3.2015 को दिल्ली में 'ट्विटर संवाद' सेवा की शुरुआत कर दी। इस सेवा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सात राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कुछ मंत्रालयों के ट्विटर संदेश आपके मोबाइल पर मुफ्त उपलब्ध होंगे।

पीएम ने किया ट्वीट : पीएम ने ट्वीट कर कहा, 'आओ अपना संपर्क और मजबूत करें। उन्होंने कहा कि 011-30063006 पर मिस्ड कॉल करें और मेरे ट्वीट एसएमएस के जरिये अपने मोबाइल पर पाएं। प्रधानमंत्री ने ट्विटर के सीईओ के साथ सामाजिक मामलों में ट्विटर के मददगार हो सकने वाले उपायों के बारे में न सिर्फ बात की बल्कि उनके साथ तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के हवाले से कहा गया कि यह सेवा 16 ट्विटर हैंडल में आ गई है।

ऐसे काम करेगा 'ट्विटर संवाद' : ट्विटर संवाद को यूज करने के लिए यूजर्स को नीचे दिए गए हर ट्विटर अकाउंट के लिए जारी फोन नंबर पर एक मिस्ड कॉल देनी होगी। जैसे पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट के लिए यूजर्स को 011-30063006 पर एक मिस्ड कॉल करनी होगी। मिस्ड कॉल देने के तुरंत बाद यूजर्स के मोबाइल पर पूरे दिन क्योरेटेड ट्वीट्स मिलेंगे जिससे वे नेताओं और सरकारी एजेंसियों के संपर्क में रह सकेंगे। किसी इमरजेंसी पोजीशन में या जन घोषणा की स्थिति में अकाउंट होल्डर्स तुरंत सभी रजिस्टर्ड यूजर्स को अपडेट भी भेज सकेंगे। ऐसे जुड़ सकते है आप : • @Narendramodi - पीएम का व्यक्तिगत अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30063006) • @PMOIndia- पीएम मोदी का ऑफिशियल अकाउंट मिस्डकाल करें (011-3006300) • @adgpi - ऐडिशनल डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पब्लिक इनफॉर्मेशन, आईएचक्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30496116) • @RailMinIndia - रेलवे मंत्रालय का ऑफिशियल अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30496222) • @anandibenpatel - गुजरात की सीएम आनंदीबेन पटेल का व्यक्तिगत अकाउंट (011-30496050) • @CMoKarnataka - कर्नाटक के सीएम सिद्दारमैया का अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30494737) • @ncbn - आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू का व्यक्तिगत अकाउंट मिस्डकाल करें (011-3049567) • @Telangana CMO - तेलंगाना के सीएम कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव का ऑफिशियल अकाउंट, मिस्डकाल करें (011-30495868) • @yadavAkhiilesh - यूपी के सीएम अखिलेश यादव का अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30083380) • @UPGovt- यूपी सरकार का ऑफिशियल अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30496353) • @NitishkumarJDU - बिहार के

सीएम नीतीश कुमार का अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30082828) • @MealIndia- मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स-भारत, सैयद अकबरुद्दीन का ऑफिशियल अकाउंट मिस्डकाल करें (011-30495969)

(साभार : आइनेक्स्ट, 26.3.2015)

बिहार : पर्यटन नीति की गाड़ी अटकी

राज्य सरकार ने 2011 में अपनी औद्योगिक नीति में पर्यटन को आर्थिक विकास के लिए अहम क्षेत्र के रूप मान्यता दी थी। राज्य सरकार की योजना इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने की है। ताकि राज्य में पर्यटन सुविधाओं में इजाफा हो सके। इसके लिए राज्य सरकार ने 2012 में एक नई नीति बनाने का फैसला लिया। सूत्रों की मानें तो इस नीति का मसौदा भी बीते साल ही तैयार हो गया। लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इसे अपनी मंजूरी नहीं दी है। इस नई नीति से उद्योग विभाग को पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकर्षित करने में मदद की उम्मीद है। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'इस बारे में हमने काम पूरा कर लिया है। लेकिन अब तक इसे कैबिनेट के सामने पेश नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने अब पर्यटन के क्षेत्र में एक नई नीति बनाने का फैसला किया है। यह नीति खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए बनाई गई हमारी नीति की रूप रेखा पर बनाई गई है। इसीलिए हमें इस नीति पर निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है।'

नई नीति के तहत राज्य सरकार ने निवेशकों को खासी रियायतें देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक इस नीति में राज्य सरकार निवेशकों को कुल निवेश का 35 फीसदी का अनुदान के रूप में दे सकती है। जिसमें जमीन की कीमत भी शामिल होगी। हालांकि इसके तहत सरकार अधिकतम 75 लाख रुपये तक का ही अनुदान देगी। राज्य सरकार ने नए होटलों को विलासिता कर में भी पूरी तरह से रियायत देने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत होटलों को खाने-पीने के सामान पर भी वैट से रियायत देने के बारे में राज्य सरकार विचार कर रही है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार निवेशकों को परियोजना के वास्ते बैंकों से लिए गए कर्ज पर भी रियायत देने का प्रस्ताव है। राज्य औद्योगिक नीति के तहत मिलने वाली रियायतों का फायदा भी देगी।

बिहार के उद्योग संघों ने इस बारे में राज्य सरकार से जल्द कदम उठाने का आग्रह किया है। **बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष ओ० पी० साह ने कहा, राज्य सरकार ने अपनी नई औद्योगिक नीति के तरत राज्य के विकास के लिए पर्यटन पर खास ध्यान देने का फैसला लिया था। लेकिन इस नीति की घोषणा जल्द करनी चाहिए, ताकि निवेशक राज्य की तरफ रुख कर सकें।'**

(साभार : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 30.3.2015)

नक्शा पारित करने को होंगे कंसल्टेंट

नए नगर आयुक्त जय सिंह ने कहा कि निगम में नक्शा पास करने के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। इससे जल्दी ही नक्शा पास होने लगेगा व शहर में भवन निर्माण के काम में तेजी आएगी। जनहित के काम में किसी तरह की बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के विवाद को निगम के कार्यों में अवरोध नहीं बनने दिया जाएगा। बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग और सरकार को पत्र लिखा जाएगा।

ये बातें उन्होंने नगर आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद कहीं। जय सिंह ने कहा कि वास्तुविदों व अभियंताओं की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाले गए हैं। नियुक्ति के बाद वास्तुविदों का पैनल बनाया जाएगा। इसके बाद कंसल्टेंट ही बिल्डिंग बाईलॉज के अनुसार नक्शा पास करेंगे। उन्होंने कहा कि शहर के अवैध भवनों पर भी कोर्ट के आदेशानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि शहर के लोग और सरकार, सभी पटना को साफ- सुथरा और सुविधायुक्त देखना चाहते हैं। इसके लिए जल्द ही डोर-टू-डोर कचरा प्रबंधन, सफाई उपकरणों की खरीद और नाला उड़ाही जैसे काम पूरे किए जाएंगे। दोबारा जलजमाव न हो, इसका प्रयास किया जाएगा।

सभी प्रमुख सड़कों पर लगेंगी स्ट्रीट लाइट : नगर आयुक्त जय सिंह ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख 12 सड़कों पर अभी 739 स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। और 261 लाइट लगाने के लिए स्थल का चयन किया जा रहा है। लाइटों को शीघ्र लगाने और उनकी देखरेख के लिए बुडको के अभियंताओं के साथ बैठक हो चुकी है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.4.2015)

राहत, नहीं बढ़ेगा होल्डिंग टैक्स

होल्डिंग टैक्स के दायरे में आने वाली सूबे की तकरीबन पांच करोड़ की आबादी को इस साल होल्डिंग टैक्स की बढ़ी दरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अप्रैल 2015 से होल्डिग टैक्स की नई दरें प्रभावी होनी थी। लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स बोर्ड का गठन समय पर न होने के कारण सरकार ने होल्डिंग टैक्स की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव वापस ले लिया है। लेकिन, दूसरी ओर पुरानी दरों पर ही होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए सरकार ने संविदा पर टैक्स कलेक्टरों की बहाली का फैसला जरूर किया है। संविदा पर नियुक्त टैक्स कलेक्टरों को बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में सरकार पुरस्कृत भी करेगी।

(साभार : दैनिक जागरण, 1.4.2015)

हल्दिया-पटना जगदीशपुर गैस पाइपलाइन मंजूर

केन्द्र सरकार ने दस हजार करोड़ रुपये की लागत से हल्दिया से पटना होते हुए जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन स्थापित करने की मंजूरी दे दी जिससे बिहार और उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक फायदा होगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में हल्दिया से जगदीशपुर के बीच 2000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद बताया कि इस पाइपलाइन से पूर्वी भारत के गोरखपुर, वाराणसी, कोलकाता, पटना जैसे शहरों के लोगों को बड़ा फायदा होगा। इससे घरों में पाइप के जरिए गैस की आपूर्ति की जा सकेगी और एक करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिल सकेगी। अभी तक 40-45 लाख परिवारों को ही यह सुविधा उपलब्ध है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2015)

2016 तक गंगा किनारे रिवर फ्रंट

पटना में कलेक्ट्रेट घाट से लेकर गुलबी घाट के बीच गंगा रिवर फ्रंट का काम जून 2016 तक पूरा कर लिया जाएगा। 256 करोड़ रुपये की इस योजना में से अब तक 26 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं। विकास आयुक्त एसके नेगी और नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने गंगा घाटों का मुआयना किया। विकास आयुक्त ने निरीक्षण के क्रम में कार्य में और तेजी लाने तथा गुणवता का पूरा ध्यान रखने का निर्देश दिया। बाद में प्रधान सचिव नगर विकास ने बताया कि कलेक्ट्रेट घाट से लेकर गुलबी घाट के साढ़े छह किलोमीटर लंबाई में रिवर फ्रंट विकसित किया जा रहा है। योजना के तहत अलग-अलग घाटों में से किसी घाट पर ऑडिटेरियम, किसी पर कैफेटेरिया, पार्क के साथ ही पांच किलोमीटर का पाथ-वे बनाया जाएगा। इस पाथ पर व्यक्ति पैदल चल सकेंगे।

(दैनिक जागरण, 1.4.2015)

मुंगेर गंगा रेल पुल पर ट्रेनें जल्द

हाजीपुर रेलवे जोन के महा प्रबंधक ए० के० मित्तल ने कहा कि मुंगेर गंगा रेल पुल पर 2015-16 तक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। खगड़िया रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के दौरान उन्होंने मुंगेर रेल पुल की प्रगति का आकलन भी किया और कहा कि रेल सह सड़क पुल के लिए सभी गटर बन चुके हैं।

खगड़िया में निरीक्षण के दौरान श्री मित्तल ने कहा कि मुंगेर रेल पुल पर ट्रेक भी बैठा दिए गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष में ही रेल पुल चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने धमारा घाट स्टेशन पर रेल ओवर ब्रिज के जल्द निर्माण की भी बात कही। कहा कि हादसे के बाद स्टेशन को ठीक करने का काम शुरू हो चुका है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 28.3.2015)

निर्यात बढ़ाने के लिए नई सौगात

केन्द्र सरकार की 2015-2020 के लिए पहली विदेश व्यापार नीति में अगले पांच साल में देश से वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात को करीब दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके मुताबिक 2020 तक देश का निर्यात बढ़कर करीब 900 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही नई नीति में निर्यातकों और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को कई तरह के प्रोत्साहन देने की घोषणा की गई है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामन ने विदेश व्यापार नीति जारी करते हुए कहा, 'मौजूदा डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत निर्यात सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है। साथ ही निर्यात प्रोत्साहन मानदंडों को सब्सिडी पर निर्भरता कम कर ज्यादा व्यवस्थित बनाने की दरकार है। ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे निर्यात और

सेवाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो सकें । हमें गुणवत्ता और मानदंडों पर ध्यान देने के साथ ही शून्य दोष वाले उत्पाद तैयार करने होंगे। ब्रांड इंडिया को भरोसे और गुणवत्ता का पर्याय बनाना होगा।'

विदेश व्यापार नीति की खास बातें : • वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात 2019-20 तक 900 अरब डॉलर तक बढ़ेगा • वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 3.5 फीसदी होगी • भारत वस्तु निर्यात योजना तथा भारत सेवा निर्यात योजना शुरू • मूल्यवर्द्धन वाले निर्यात के लिए एमईआईएस के तहत मिलेगा ज्यादा प्रोत्साहन • पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने की पहल

(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 2.4.2015)

चैम्बर के नये सदस्यों का स्वागत

मेसर्स त्रिमूर्ती फ्लोर मिल प्रा० लि०, शहादरा, पटना सिटी के डायरेक्टर श्री अरविन्द कुमार शाही एवं श्री अभिषेक सिन्हा को सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करते चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह। साथ में चैम्बर के अन्य पदाधिकारीगण।

दिनांक 31 जनवरी, 2015 को कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिन सदस्यों की सदस्यता स्वीकृत हुई थी, उनका दिनांक 24 मार्च, 2015 को सम्पन्न कार्यकारिणी समिति की बैठक में चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रदान कर स्वागत किया। 31 जनवरी, 2015 को जिनकी सदस्यता स्वीकृत हुई थी, वे हैं:- (1) मेसर्स शाकम्भरी एग्रोफुड्स इण्डस्ट्रीज, मालसलामी, पटना सिटी (2) श्री गौतम बिजपुरिया, एडवोकेट (टैक्स कंसल्टेंट), कचौड़ी गली, पटना सिटी (3) मेसर्स बालाजी फार्मा, कंकड़बाग, पटना (4) मेसर्स एम० बी० इण्डस्ट्रीज, बेला, मुजफ्फरपुर (5) मेसर्स सवेरा, खेतान सुपर मार्केट, पटना (6) मेसर्स त्रिमूर्ती फ्लोर मिल प्रा० लि०, शहादरा, पटना सिटी। उक्त बैठक में मेसर्स त्रिमूर्ती फ्लोर मिल प्रा० लि०, शहादरा, पटना सिटी को छोड़कर अन्य के प्रतिनिधि अपरिहार्य कारणवश इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाये।

ओपनिंग डे के पहले घंटे में नहीं बदलेगी यात्रा तिथि

वेटिंग टिकट लेने के बाद यात्रा तिथि में बदलाव के नियमों में रेलवे बोर्ड ने संशोधन किया है। ओपनिंग डेट (यात्रा तिथि से 60 दिन पहले) में इस नियम के दुरुपयोग और आम लोगों को हो रही परेशानी की देखते हुए बोर्ड ने सभी जोनल महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है कि ओपनिंग डेट के पहले घंटे में यात्रा तिथि में तब्दीली रोकी जाए। हालांकि बाद में ट्रेन खुलने के 48 घंटे पहले तक यात्रा तिथि में बदलाव किया जा सकता है। रेलवे बोर्ड ने नियमों के संशोधन के लिए सीआर आई एस (सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स) को भी निर्देश दे दिए हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार नए नियम रेलवे में लागू भी हो गए हैं। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 14.3.2015)**

वरीय अधिवक्ता श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह का निधन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने पटना उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता एवं चैम्बर के मानद सदस्य श्री सिद्धेश्वरी प्रसाद सिंह उर्फ सिद्धी बाबू के आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री सिंह का निधन दिनांक 25 मार्च, 2015 को हो गया। वे 96 वर्ष के थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री ओ० पी० साह ने कहा कि श्री सिंह एक सुप्रसिद्ध कानूनविद के साथ-साथ कई एक सामाजिक संगठनों से भी जुड़े थे। श्री सिंह चैम्बर के मानद सदस्य के रूप में पिछले दो दशकों से जुड़े थे और समय-समय पर उन्होंने चैम्बर का मार्गदर्शन किया है। उनका जीवन सदैव मानवता एवं सामाजिक सेवा के लिए समर्पित रहा। एक सफल अधिवक्ता के रूप में उनका कार्य काफी सराहनीय एवं अनुकरणीय रहा। उनका निधन एक अपूरणीय क्षति है।

श्री साह ने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को चिर स्थायी शान्ति प्रदान करें एवं उनके शोक संतप्त परिवार को हुई इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति दें।

एक अप्रैल से महिलाओं और वृद्ध को लोअर बर्थ में आरक्षण

रेलवे ने महिला व वृद्ध यात्रियों को लोअर बर्थ उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था बनाई है। अब सभी ट्रेनों के हर कोच में बुजुर्गों व 45 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए दो-दो लोअर बर्थ अलग से आरक्षित रखने का निर्देश जारी किया गया है। यह व्यवस्था एक अप्रैल से ही लागू होगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड की ओर से सभी मंडल व जोन को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया गया है। इससे महिला यात्रियों को सहूलियत होगी।

महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता : इनना ही नहीं यदि वृद्ध, निश्शक्त, गर्भवती व 45 वर्ष से अधिक उम्र को महिलाओं को लोअर बर्थ नहीं मिल सका और रनिंग ट्रेन में अगर लोअर बर्थ खाली रह गया है तो सबसे पहले उन्हीं को लोअर बर्थ मुहैया कराने को कहा गया है। इसके लिए सभी टीटीई को दिशा निर्देश दिया गया है। यह व्यवस्था एसी प्रथम श्रेणी व चेयरकार में नहीं मुहैया कराई गई है।

(साभार : दैनिक जागरण, 26.3.2015)

दनियावां-बिहारशरीफ खंड पर चली मालगाड़ी

बिहारशरीफ-राजगीर से पटना का रेल सफर हो जाएगा 16 किमी कम

31 मार्च 2015 से दनियावां-बिहारशरीफ रेलखंड पर मालगाड़ी का चलना शुरू हो गया। राजगीर से पटना की ओर जाने वाली मालवाहक ट्रेनें अब बख्तियारपुर की बजाय दनियावां होते हुए जाएंगी। पटना की दूरी 16 किलोमीटर कम हो जाएगी। इस नई रेलखंड से होकर मालगाड़ी के चलाये जाने से राजगीर-बख्तियारपुर रेलखंड पर का ट्रैफिक लोड घेटगा। फलत : पैसेंजर ट्रेनें समय पर चल सकेंगी। दनियावां से बिहारशरीफ की 38.3 किलोमीटर की दूरी को तय करने में मालगाड़ी को 23 मिनट का समय लगेगा। इस रेलखंड की सीआरएस (कमिश्नर ऑफ रेलवे, सेफ्टी) द्वारा जांच के बाद पैसेंजर ट्रेनें चलायी जाएंगी। इसमें दो से तीन माह का समय लग सकता है। शुरूआत में एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चलाने की योजना है। इस रेलखंड के लिए जोड़ी पैसेंजर ट्रेन रेलवे ने अलॉट भी कर दिया है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 1.4.2015)**

महंगे बीमा पर ट्रांसपोर्टर भड़के

थर्ड पार्टी मोटर बीमा के प्रीमियम में 1 अप्रैल से भारी बढ़ोतरी होनी है। व्यावसायिक वाहनों के थर्ड पार्टी बीमा के प्रीमियम में औसतन 80-90 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। ट्रांसपोर्टर इस बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं और बीमा कंपनी और नियामक को चेतावनी भी दे रहे हैं कि प्रीमियम में बढ़ोतरी हुई तो वे चक्का जाम करेंगे। **(विस्तृत : बिज़नेस स्टैंडर्ड, 1.4.2015)**

EDITORIAL BOARD

Editor
O. P. Tibrewal
Secretary General

Ramchandra Prasad
Chairman
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. Dubey
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-3200646, 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org
Design & Printed by : Sharada Enterprises, Patna, Ph.:0612-2690803, 2667296